

प्रेषक,

टी० के० फन्त,
संयुक्त सचिव,
उत्तरांचल शासन ।

सेवामे,

प्रभारी मुख्य अभियन्ता स्तर-1,
लो०नि०वि०, देहरादून ।

लोक निर्माण अनुभाग-2

देहरादून, दिनांक 25 मई, 2005

विषय:- वित्तीय वर्ष 2005-2006 मे निर्माणाधीन मार्ग के कार्यों हेतु प्राविधानित धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रमुख सचिव, वित्त अनुभाग-1 के पत्र संख्या- 527A/ XXVII (1)/वित्त अनुभाग-1/2005, दिनांक 26 अप्रैल, 2005 के अनुपालन में एवं आपके पत्र संख्या-101/01 बजट (मार्ग कार्य-रा.से.)-1/2005-06 दिनांक 6.4.2005 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लोक निर्माण विभाग के निर्माणाधीन मार्ग (राज्य सेक्टर) के कार्यों हेतु आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रु० 2450000 हजार (रु० दो अरब पैतालीस करोड मात्र) की धनराशि में से नाबार्ड द्वारा स्वीकृत कार्यों से भिन्न निर्माणाधीन मार्गों के कार्यों हेतु रु० 1350000 हजार (रु० एक अरब पैतीस करोड मात्र) एवं नाबार्ड द्वारा आर०आई०डी०एफ० 8, 9 व 10 योजना के अन्तर्गत स्वीकृत मार्गों के चालू कार्यों हेतु रु० 700000 हजार (रु० सत्तर करोड मात्र) इस प्रकार कुल रु० 2050000 हजार (रु० दो अरब पाँच करोड मात्र) की धनराशि व्यय हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

2- उक्त स्वीकृत धनराशि का सी.सी. एल. के आधार पर कोषागार से साख सीमा हेतु निर्धारित नियमान्तर्गत ही आहरण किया जायेगा, यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि स्वीकृत धनराशि का कार्यवार/खण्डवार आबंटन ऐसी चालू योजनाओं पर शासन की सहमति के प्रथमतः किया जायेगा, जिसमें 75 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो गया है, जिन खण्डों में 75 प्रतिशत या उससे अधिक के कार्य अवशेष नहीं हैं, उन खण्डों में 50 प्रतिशत से अधिक के कार्य किये जायेगे, कार्यवार/खण्डवार आबंटन कर संकलित प्रस्ताव शासन को एक सप्ताह में उपलब्ध कराया जायेगा। नाबार्ड द्वारा आर०आई०डी०एफ० 8 व 9 के अन्तर्गत स्वीकृत अवशेष कार्यों को इस वित्तीय वर्ष में पूर्ण किया जाना होगा।

3- यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि व्यय चालू कार्य पर कार्य की पूर्व अनुमानित लागत की सीमा तक ही किया जाये, कार्य पर व्यय लो०नि०वि० के मानक विषयक शासनादेश के अनुरूप ही कराया जायेगा, उक्त धनराशि के आहरण के पूर्व विगत वर्ष स्वीकृत समस्त धनराशि का उपयोग सुनिश्चित कर लिया जायेगा।

4- व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय । निर्माण कार्य पर व्यय करने से पूर्व प्रत्येक कार्य के आगणनों/पुनरीक्षित आगणनों पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ-साथ विस्तृत आगणनों पर सक्षम प्राधिकारी की तकनीकी स्वीकृति भी अवश्य प्राप्त कर ली जाय । कार्य करते समय टैण्डर/कुटेशन विषयक नियमों का अनुपालन किया जायेगा ।

5- कार्य की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु संबंधित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

Nic
160

- 6- स्वीकृति के एक माह के अन्दर अब तक स्वीकृत धनराशि के विपरीत कार्यों का विवरण एवं वित्तीय तथा भौतिक प्रगति का विवरण शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। वर्ष 2005-06 में स्वीकृत धनराशि के विपरीत कार्यों का विवरण व भौतिक प्रगति मार्च, 2006 के प्रथम सप्ताह में उपलब्ध करा दी जायेगी।
- 7- उक्त स्वीकृत धनराशि का कार्यवार आबंटन कर वित्तीय व भौतिक लक्ष्यों का विवरण प्राथमिकता के आधार पर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
- 8- इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2005-06 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-22 लेखाशीर्षक- 5054 सड़को एवं सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय -04 जिला तथा अन्य सड़कें-आयोजनागत-800 -अन्य व्यय -03-राज्य सेक्टर-01 चालू निर्माण कार्य-24 वृहत्त निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।
- 9 - यह आदेश वित्त विभाग के अ.शा. सं० 193/वित्त अनुभाग-3/05, दिनांक 13 मई, 2005 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(टी० के० पन्त)
संयुक्त सचिव।

संख्या-663 (1)/111(2)/05, तददिनांक।

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
- 1- महालेखाकार (लेखा प्रथम) उत्तरांचल, इलाहाबाद / देहरादून।
 - 2- आयुक्त कुमायू मंडल, पौड़ी/नैनीताल।
 - 3- समस्त जिलाधिकारी/ कोषाधिकारी, उत्तरांचल।
 - 4- वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
 - 5- निदेशक राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तरांचल, देहरादून।
 - 6- मुख्य अभियन्ता, गढ़वाल/कुमायू क्षेत्र, लो०नि०वि०, पौड़ी/ अल्मोडा।
 - 7- वित्त अनुभाग-3/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तरांचल शासन।
 - 8- लोक निर्माण अनुभाग-1/3 उत्तरांचल शासन।
 - 9- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(टी० के० पन्त)
संयुक्त सचिव।